

राजनीतिक व्यवस्था में जातिवाद की भूमिका

SARLA DEVI

MA (ENG.Literature), MA (POL Science), NET (POL Science)
ASSISTANT PROFESSOR (POL Science)

शोध सार :-

जाति शब्द को समाज के अलग-अलग वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है। जाति एक अंतर्वैवाहिक समूह है जो अपने सदस्यों पर कुछ प्रतिबंध रखता है। इस अर्थ में जातिवाद यह कहता है कि हर एक जातिय समूह दूसरे से अलग समूदाय है इसलिए ही अलग अलग जातिय समूह एक दूसरे से अलग है तथा उनके हित भी एक दूसरे से अलग है। जाति एक सामाजिक संरचना है जो अति प्राचीन काल से ही भारत में प्रचलित है। आधुनिक पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं के साथ लोकतंत्र स्वीकार करने के बावजूद जातिवाद समाप्त नहीं हुआ। वोट राजनीति ने जातिवाद को और ज्यादा बढ़ाया है। अपनी जाति के संगठन का उनके माध्यम से राजनीतिक वजूद बनाने का प्रयास किया है। जातिय संगठनों की उचित अनुचित मांगों का समर्थन कर उन्हें अपना वोट बैंक बनाने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार वोट राजनीति ने न केवल जातिय भावनाएं बढ़ाने का प्रयास किया बल्कि आपसी जातीय तनाव भी पैदा किया है। मत के अनुसार यह पारिवारिक व्यवसाय से उत्पन्न हुई है। सामप्रदायिक मत के अनुसार जब विभिन्न सम्प्रदाय संगठित होकर अपनी अलग जाति का निर्माण करते हैं। तो इसे जाति प्रथा की उत्पत्ति कहते हैं। परम्परागत मत के अनुसार यह प्रथा द्वारा विभिन्न कार्यों की दृष्टि से निर्मित किये गये हैं।

भारत में जातिवाद:-

भारत में जाति चिरकालीन सामाजिक व्यवस्था है।

प्राचीन समय की तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के विभिन्न वर्गों को नियमित करने के लिए वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ था जो कर्म व व्यवसाय के सिद्धांत पर आधारित थी। बहुजातिय विविधापूर्ण समाज के व्यवस्थित समन्वय व राजनीतिक परिस्थितियों में अनुकूल मानी गई थी। इसमें कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाने से यह भेदभाव पूर्ण व विखण्डन कारी प्रवर्ति पहले जाति प्रथा और आधुनिक काल में जातिवाद के रूप में विकसित हुई जिसने भारत की एकता व अखण्डता को गम्भीर चुनौती प्रदान की है अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाते हुए इस विभेद कारी सामाजिक व्यवस्था का निहित स्वार्थों के लिए प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया उन्होंने इसका अपने औपनिवेशिक हित में फायदा उठाने का प्रयत्न किया इसे और अधिक भड़काया अंग्रेजों द्वारा दलित वर्गों के लिए भी प्रथक निर्वाचन की

व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई जिसका गांधी जी ने विरोध किया इसी मुद्दे पर गांधी जी व अंबेडकर जी के बीच पूना पैक्ट हुआ। जिसमें इन वर्गों के उचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु स्थान आरक्षित करने की व्यवस्था स्वीकार की गयी। अम्बेडकर जी ने प्रथक निर्वाचन का आग्रह छोड़ दिया प्रथक निर्वाचन का उद्देश्य हिन्दूओं में भी उच्च एवं निम्न जातियों में फूट पैदा करना था जिसको राष्ट्र पिता महात्मा गांधी एवं महान नेता अम्बेडकर दोनों ने समझा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद :-

ऐसा माना जाने लगा था कि देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित होने के पश्चात जातिवाद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। के.के. मेनन के अनुसार "स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का प्रभाव पहले की तुलना में बढ़ गया है।"

मोरिस जॉन्स "जाति के लिए राजनीति का महत्व एवं राजनीति के लिए जाति का महत्व बढ़ा है।" लोकतंत्र के

साथ इनकी स्थापना के साथ यह धारणा बनी थी कि धीरे धीरे जातिवाद का अंत हो जाएगा।

शब्दार्थः— जातिवाद, प्रतिनिधित्व, लोकतांत्रिक व्यवस्था, औपनिवेशिक हित।

जाति एक ऐसा सामाजिक समूह होता है जो दूसरों से अपने को अलग मानता है। जिसकी अपनी विशेषता होती है, किन्तु अपनी परिधि में ही वैवाहिक संबंध करते हैं।

जय प्रकाश नारायण “ भारत में जाति एक महत्वपूर्ण दल है।” जातिय संगठन दबाव समूह में काम करते हैं जातिवाद लोगों में एकता व अखण्डता एवं सामूहिकता की भावना पैदा करती है। राजनीतिक जागृति व सक्रियता के साथ साथ खानपान व वैशभूषा रहन सहन आदि में समानता पैदा होती है। **जय प्रकाश नारायण** “जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है।” वहीं के के मेनन कहते हैं कि “स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति प्रभाव पहले की अपेक्षा बढ़ा है।” जातिय संगठन अपने हितों के अनुसार निर्णय करने तथा अपने हितों के प्रतिकूल होने वाले निर्णयों को रोकने हेतु निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में जाति की विशेष भूमिका होती है। राजनीतिक दल अपने आन्तरिक संगठनात्मक चुनावों एवं नियुक्तियों में भी जातिय समीकरण का ध्यान रखती हैं। कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों में आन्तरिक रूप से भी जातीय आधार पर कई गुट पाए जाते हैं। जो शक्ति प्रतिस्पर्धा में लगे रहते हैं। राजनीतिक दलों में जातिगत आधार पर प्रत्याशियों को निर्णय होता है। भारत में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में जातिवाद सर्वाधिक प्रभावशाली रूप से हावी रहता है सभी राजनीतिक दल जातिय समीकरणों को अपने पक्ष में बनाए रखने हेतु बहुमत प्राप्त होने पर सरकार निर्माण के लिए मंत्रीमण्डल निर्माण करते समय भी जातीय संतुलन का विशेष ध्यान रखता है। जातीय संगठन राजनीतिक व्यवस्था पर दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। आरक्षण से वंचित जातियों के संगठन

आरक्षण बनाये रखने हेतु निरंतर सरकार पर दबाव डालते हैं। **मेयर** “जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं के अलावा प्रशासन में भी जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गयी है। अनसूचित जाति अनसूचित जनजाति के अलावा अन्य पिछड़े वर्गों को भी २७ प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अखिल भारतीय राजनीति के बजाय राज्य की राजनीति में जाति की ज्यादा सक्रिय भूमिका रहती है। बिहार, उत्तरप्रदेश, तमिलनाडू, केरल, मध्यप्रदेश, आन्ध्रप्रदेश, राजस्थान आदि की राजनीति का विश्लेषण बिना जातिगत गणित के किया ही नहीं जा सकता। उत्तर प्रदेश एवं बिहार तो जातिगत राजनीति की मिशाल बन चुके हैं। राजनीतिक दल एवं उम्मीदवार भी चुनाव प्रचार में जाति का खुलकर प्रयोग करते हैं। चुनावों के समय जातीय समीकरण बैठाये जाते हैं। चुनाव प्रचार में भी नेताओं द्वारा जाति का ही सहारा लिया जाता है। और लोक जातीय संगठनों में भी उच्च पदों पर पहुंचे गए वे भी राजनीति में भी अच्छे स्थान प्राप्त करने में सफल हुए।

भारत में जातिगत राजनीति की विशेषताएं हैं। जैसे जातीय संघों अथवा संगठनों ने जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है। शिक्षा, शहरीकरण औद्योगिक आधुनिकीकरण तथा लोकतंत्रीय व्यवस्था के बावजूद जातिवाद की भावना एवं एकीकरण को बल मिला है।

प्रभाव :- भारतीय राजनीति में जातिवाद के सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव भी दिखते हैं।

सकारात्मक प्रभाव:- जाति एवं राजनीति के संबंध ने लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। विकसित संचार की तकनीक के कारण एक दूसरे से संपर्क बनाए रखते हैं। इससे लोगों में सामाजिकता एवं एकता की भावना का विकास होता है। जाति की राजनीति ने अधिक लोगों को राजनीतिक सक्रियता पैदा की है। जातीय सक्रियता के कारण समाज में उन जातियों को महत्व भी बढ़ा है जो पहले राजनीतिक,

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से शक्ति विहिन थी। जाति की राजनीति से समाज की संस्कृति को भी प्रभावित किया है। समाज की सभी जातियों के खान-पान, वेशभूषा, रहन-सहन, आचार-विचार में निम्न जातियाँ, उच्च जातियों का अनुसरण करती है। जिससे समानता बढ़ती है।

रूडोल्फ तथा रूडोल्फ :- जाति की राजनीति से जाति के मध्य मतभेदों को कम किया है। और विभिन्न जातियों के सदस्यों में समानता आयी है।

नकारात्मक प्रभाव :- जातिवाद से समाज में संघर्ष भी पैदा होता है।

डी०आर गाडगिल :- जाति का प्रभाव प्रजातंत्र में सहायक नहीं है।

डॉ० आशीर्वादम् :- भूतकाल में जाति के चाहे जो भी लाभ हो लेकिन वर्तमान प्रगति में जातिवाद एक बाधक है। इससे राष्ट्रीय हित का नुकसान होता है। रूढ़िवादिता बढ़ती है। बंधुत्व एवं एकता की भावना को हानि पहुँचती है। गुर्जर आन्दोलन के दौरान गुर्जर व मीणा जाति के बीच कुछ क्षेत्रों में पैदा तनाव इसका उदाहरण है। इससे संघर्ष व अशांति पैदा होती है। जातिवाद के आधार पर विजयी हुए उम्मीदवार के द्वारा देश का शासन अयोग्य व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। जिससे देश का भला नहीं होता है। अल्पसंख्यक जाति या समुदाय के लोगों में असुरक्षा की भावना का विकास होता है।

आज राष्ट्रीय हितों की अपेक्षा जातिगत हितों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है।

समाजशास्त्री M.N. श्रीनिवासन :- परम्परावादी जाति व्यवस्था ने प्रगतिशील और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था को इस तरह प्रभावित किया है कि ये राजनीतिक संस्थाएँ अपने मूल रूप में कार्य करने में समर्थ नहीं है।

डी०आर गाडगिल :- “क्षेत्रीय दबावों से कहीं ज्यादा खतरनाक बात यह है कि वर्तमान काल में जाति

व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में बाधक सिद्ध हुई है।” अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है।” लोकतंत्र व्यक्ति को ईकाई मानता है, किसी जाति या समूह को नहीं।

सारांश :-

जब एक वर्ग पूर्णतः आनुवांशिकता आधारित होता है तो हमउ से जाति कहते है। जातिवाद लोगो में एकता एवं सामूहिकता की भावना पैदा करती है। आधुनिक भारतीय समाज में जातिगत भेद-भाव केंसर एवं एड्स जैसे भयंकर रोगों की तरह सर्वत्र फैल गया है, जिसका निदान असम्भव है। यह केवल व्यक्ति-व्यक्ति के बीच खाई ही पैदा नहीं करती अपितु राष्ट्रीय एकता के मार्गमें भी बाधा उत्पन्न कर रही है। अतः जातिवाद देश, समाज और राजनीति के लिए बाधक है।

सन्दर्भ ग्रन्थ :-

1. **रजनी कोठारी :-** “फास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स” (भारतीय राजनीति में जाति)
2. **मजूमदार एवं मदान :-** “जाति एक बन्द वर्ग है।”
3. **लॉयड एवं सुसैम रूडोल्फ :-** “जाति संगठन भारत जैसे परम्परागत समाज में आधुनिकता के अभिकर्ता है।
4. **M.N.श्रीनिवासन :-** “प्रभुत्व जाति का विचार”
5. **मोरिस जोन्स :-** “जिसे राजनीति में जातिवाद कहा जाता है, वह जातियों के राजनीतिकरण से अधिक और कुछ नहीं है।”